

महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रेन से टकरा कर युवक-युवती हुई घायल, पुलिस जांच में जुटी महासमुंद (आरएनएस)। जिले के स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास एक युवक युवती ट्रेन से टकरा गए। सुबह साढ़े चार बजे घटना की जानकारी लोको पायलट ने दी। जिस पर तुरंत स्थानीय अमला मौके पर पहुंचा। तब तक दोनों की सांसें चल रही थी। तुरन्त इन्हें 112 की सहायता से जिला अस्पताल भर्ती किया गया। इनका उपचार जारी है। दोनों की पहचान नहीं हुई है। बताया गया है कि सुबह टिटलागढ़ से मालगाड़ी रायपुर की ओर आ रही थी। महासमुंद होम सिग्नल और बांधा पुलिया के बीच ये अचानक ट्रेन के सामने पटरी पर आ गए। ट्रेन देखकर भयवश ये पटरी पर ही लेट गए। इंजन के सामने लगे गार्ड से इनके शरीर में चोट आई है। हालांकि ट्रेन की गति कम होने से अधिक चोट नहीं लगी। ये आत्महत्या की नीयत से आये थे, या दुर्घटना हुई है। ये जांच का विषय है। बताया गया है कि उपचार के बाद दोनों से पूछताछ होगी।

किराना दुकान के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान खाक

जांजगीर-चांपा (आरएनएस)। जांजगीर-चांपा बाराद्वार के नेहरू चौक स्थित एक किराना दुकान के तीसरे मंजिल में लगी भीषण आग से लाखों रूपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग दुकान की तीसरी मंजिल में लगी जहां गोदाम है। सूचना पर मौके पर आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशकत के बाद आग बुझाई। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर को बाराद्वार नेहरू चौक में स्थित व्यापारी अनिल अग्रवाल के 3 मंजिला मकान के तीसरे मंजिल में से आग की लपटें और धुएँ का गुब्बारा उठने लगा। जिसमें नीचे में व्यापारी किराना का व्यवसाय करता है तथा दूसरे माले में व्यापारी का परिवार रहता है। गुरुवार दोपहर करीब 11 से 12 बजे के बीच किराना दुकान के तीसरे मंजिल से धुआं उठने लगा और आग बेकाबू हो गई जिसके बाद तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटे भर की मशकत के बाद आग पर काबू पाया और एक बड़ी दुपटना टल गई। आग लगने की वजह फिलहाल तेज गर्मी और शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना में व्यापारी का लाखों का माल जलकर खाक हो गया।

विधायक प्रतिनिधि पर दुर्घर्म का आरोप: शादीशुदा महिला ने लगाया आरोप

जांजगीर-चांपा (आरएनएस)। जांजगीर-चांपा में एक विधायक प्रतिनिधि पर एक शादीशुदा महिला ने दुर्घर्म का आरोप लगाया है। महिला ने इसकी शिकयत थाने में दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार डभरा क्षेत्र के रामभांडा निवासी ताराचंद साहू एक विधायक के प्रतिनिधि हैं। शादी होने के बाद भी ताराचंद का एक युवती से चक्कर चल रहा था। शिकायत करने महिला ने बताया कि 2014 से उसके और ताराचंद के बीच संबंध थे। इसके बाद साल 2022 में उसकी शादी रायगढ़ हो गई, लेकिन ताराचंद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। किंतु जब महिला के पति को इसका पता चला तो मामला बिगड़ गया और उसके और ताराचंद के बीच संबंधों की बात सामने आने पर पति ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद वह अपने गांव आकर रहने लगी। महिला ने आरोप लगाया कि ताराचंद ने उससे दुर्घर्म करता रहा। शादी के बाद भी धमकी देकर संबंध बनाए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ताराचंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 तहत प्रतिनिधि के खिलाफ केस दर्ज किया है।

डाक विभाग ने मां दंतेश्वरी पर विशेष लिफाफा जारी किया

जगदलपुर (आरएनएस)। डाक विभाग ने मां दंतेश्वरी पर विशेष लिफाफा जारी किया है। इसका विमोचन केंद्रीय संचार राज्यमंत्री देवू सिंह चौहान व डाक विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजीव शर्मा ने किया। शिवि कवर यानि लिफाफे बस्तर संभाग के सभी डाकघरों को दिए जाएंगे, जहां से इनकी बिक्री की जाएगी। केंद्रीय राज्यमंत्री चौहान ने बस्तर में चल रहे डाकघरों की सराहना करते कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद डाककर्मी अपने काम में जुटे हुए हैं।

कोल इंडिया का फरमान, नॉन पावर सेक्टर को होने वाली कोयले की आपूर्ति ठप्प

कोरबा। अगर किसी उद्योग की स्थापना के लिए पहली शर्त बिजली है तो बिजली उत्पादन के लिए कोयला। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ राज्य को प्रकृति ने कोयले के अकूत भंडार से नवाजा है। छत्तीसगढ़ राज्य के 250 से अधिक कैप्टिव विद्युत संयंत्रों पर आधारित उद्योगों के सुचारू संचालन के लिए प्रति वर्ष 32 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता है जो कि एएसईएल के उत्पादन का मात्र 19 प्रतिशत है। इन उद्योगों ने लगभग 4000 मेगावॉट के कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित किए हैं जिन्हें के लिए हर दिन लगभग 2 लाख टन कोयले की जरूरत है। तथ्यों के नजरिए से देश का 18 फीसदी कोयला छत्तीसगढ़ के पास है। यह लगभग



रही गतिविधियों ने कोयला को न सिर्फ महंगा कर दिया है बल्कि इसके आयात को भी पेशी बना दिया है। इन सब के बीच कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल ने अपने एक तुलसी फरमान से देश के नॉन पावर सेक्टर को होने वाले कोयले की आपूर्ति को पूरी तरह से ठप्प कर दिया है। ऐसा तब हुआ है जबकि देश में कोयला उत्पादन के आंकड़ों में सुधार हो रहा है। अब सवाल यह है कि सीपीपी आधारित उद्योगों से जुड़े मानव संसाधन, उनसे जुड़े परिवारों और पूरी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? देश ऊर्जा उत्पादन की बिन्यायी जरूरतों से ही जूझ रहा है तो फिर आखिर किस भरपूर पर उद्योगों में निवेश करने वाले लोग आगे आएंगे?

उद्योगों के सामने ऐसी चुनौती आखिर कैसे खड़ी हो गई जबकि हमारी सरकार देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर न सिर्फ मजबूत दिखती है बल्कि पूरी दुनिया के सामने देश की साख यह कहकर बनाई जा रही है कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला देश है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर पर बात की जाए तो, प्रदेश के सीपीपी और नागरिकों के हितों की अन्देखी कर एएसईएल कोयले की आपूर्ति लगातार बाहर के राज्यों को कर रहा है। 1 फरवरी, 2022 को जारी अपने एक परिपत्र के अनुसार एएसईएल छत्तीसगढ़ में सीपीपी आधारित उद्योगों के उपभोक्ताओं को मंथली

शेड्यूल क्वॉटिटी एम्पएसक्यू के मात्र 75 फीसदी कोयले का ऑर्डर बुक करने की सुविधा दे रहा था जबकि जमीनी सच्चाई यह थी कि उपभोक्ता एम्पएसक्यू का 75 फीसदी कोयला भी नहीं ले पा रहे थे। अब 14 अप्रैल, 2022 को एएसईएल ने साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, बिलासपुर को एक पत्र लिखा है जिसका मजमून यह है कि रेल मोड से नॉन पावर सेक्टर को पूरी तरह से कोयला ठप्प कर दिया जाए ताकि पावर सेक्टर को मानसून के मौसम में भी कोयले की निरंतर आपूर्ति जारी रह सके। इसका दुष्प्रभाव यह है कि छत्तीसगढ़ के सीपीपी आधारित उद्योग अब तालाबंदी की स्थिति में पहुंच गए हैं।

किसानों को मदद पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य : कृषि मंत्री

छत्तीसगढ़ में किसानों को धान और गन्ने का मिल रहा सर्वाधिक मूल्य... तमिलनाडु राज्य के कावेरी नदी किसान संरक्षण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी नीतियों को सराहा और कहा कि किसानों के हितों के संरक्षण का मॉडल राज्य है छत्तीसगढ़... रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत देखने तमिलनाडु राज्य के कावेरी नदी किसान संरक्षण समिति का प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास के दौरान इस प्रतिनिधि मंडल ने कई इलाकों का दौरा किया और किसानों से मुलाकात की। सुराजी गांव योजना के नरवा, गरूवा, चुरवा और बाड़ी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति देखी एवं रायपुर के छेरीखेड़ी स्थित मल्टी एक्टिविटी सेंटर सहित

कवर्धा जिले में गन्ने की खेती का भी मुआयना किया। तमिलनाडु के किसानों को प्रतिनिधिमंडल ने आज देर शाम छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की और तमिलनाडु राज्य तथा छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को तमिलनाडु का प्रसिद्ध ब्लैक राईस और ऑर्गेनिक गुड़ भेंट किया। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने तमिलनाडु के किसान प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी प्रतिनिधियों को शॉल एवं श्रीफल भेंटकर उनके छत्तीसगढ़ आने पर प्रसन्नता जताई। कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने बीते तीन वर्षों में खेती-किसानी को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए कई नवाचार किए हैं। यहां कई अभिनव योजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों को फसल



उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए उन्हें मदद पहुंचाने के मामले छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। यहां के किसानों को धान और गन्ना की सर्वाधिक कीमत मिल रही है। कृषि मंत्री ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीणों और किसानों की आर्थिक

स्थिति को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 7 हजार रूपए की आर्थिक मदद दी जा रही है, जो कि पीएम समान निधि के तहत मिलने वाली राशि से ज्यादा है। तमिलनाडु में भू-जल स्तर की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए कृषि मंत्री चौबे ने प्रतिनिधिमंडल को छत्तीसगढ़ सरकार के नरवा विकास कार्यक्रम को वहां अपनाए जाने का सुझाव दिया। इस अवसर पर कृषि विभाग के सचिव एवं गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉ. एस. भारतीदासन ने तमिलनाडु राज्य में कृषि की स्थिति और छत्तीसगढ़ में किसानों की बेहदारी के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। किसान प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सुन्दर विमल नाथन ने बताया कि उनका प्रतिनिधिमंडल में तमिलनाडु के अलग-अलग जिलों के किसान प्रतिनिधि शामिल हैं, जो मुख्यतः धान और गन्ना की प्रमुखता से खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों को प्रति टन गन्ना की जो कीमत मिल रही है, वह तमिलनाडु की तुलना में लगभग 6 हजार रूपए अधिक है। नाथन ने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों को मिल रहे अधिक लाभ को जानने और समझने के उद्देश्य से उनका दल छत्तीसगढ़ के दौर पर आया है। नाथन ने कृषि मंत्री से छत्तीसगढ़ में नेचुरल फॉर्मिंग का राष्ट्रीय कॉन्वेंशन आयोजित किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने खेती-किसानी में भू-जल के उपयोग को लेकर भी किसानों को जागरूक किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु राज्य में भू-जल के अनियंत्रित दोहन तथा औद्योगीकरण के चलते भू-जल स्तर 300 फीट से गिरकर एक हजार फीट नीचे चला गया है, यह स्थिति चिंताजनक है। तमिलनाडु के किसान प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर के अभनपुर विकासखण्ड स्थित आदर्श गौठान नवागांव (ल), छेरीखेड़ी स्थित मल्टी एक्टिविटी सेंटर में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित आयमूलक गतिविधियों का मुआयना किया। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के कवर्धा जिले का दौरा कर वहां किसानों द्वारा की जा रही गन्ना की खेती और भारमदेव शंकर कारखाना का भी अवलोकन किया। इस दौरान कृषि विभाग वरिष्ठ अधिकारी भी दौर पर उनके साथ मौजूद रहे।

अतिक्रमण कर बनाए गए बाउण्ड्रीवाल को हटाया निगम ने

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा के अतिक्रमण दस्ते द्वारा प्रशासन व पुलिस बल की उपस्थिति में शारदा विहार क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध बाउण्ड्रीवाल को तोड़कर हटा दिया गया, वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना अनुमति अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स विज्ञापन पोस्टर फ्लैक्स आदि को हटाने की कार्यवाही आज भी जारी रही। यहाँ उल्लेखनीय है कि आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय द्वारा अतिक्रमण व अवैध कब्जे के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नए होने वाले अतिक्रमणों पर सतत नजर रखने एवं इन पर निरंतर कार्यवाही किए जाने के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिए गए हैं। शारदा विहार क्षेत्र में एक



व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करते हुए अवैध रूप से बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करा लिया गया था, कोरबा तहसीलदार तारा सिदार, अतिक्रमण प्रभारी योगेश राठौर तथा पुलिस बल की उपस्थिति में आज निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कार्यवाही करते हुए उक्त बाउण्ड्रीवाल को जे.सी.बी.के माध्यम से तोड़कर हटाया तथा स्थल को अवैध कब्जे

से मुक्त कराया। अवैध होर्डिंग हटाने की कार्यवाही जारी- अतिक्रमण दस्ता प्रभारी योगेश राठौर ने बताया कि निगम के अमले द्वारा शहर के चौक-चौराहों, सड़कों के किनारे, डिवाइडरों में स्थित विद्युत पोल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के अवैध रूप से होर्डिंग फ्लैक्स विज्ञापन पोस्टर आदि को हटाने की कार्यवाही आज भी की गई तथा इस कड़ी में शहर के विभिन्न स्थानों के साथ-साथ सर्वमंगला जोन के मुख्य मार्गों से भी अवैध होर्डिंग पोस्टर अतिक्रमण दस्ते द्वारा हटाए गए। उन्होंने बताया कि निगम की यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

एनएच 63 पर माओवादियों 6 टिप्पर और दो जेसीबी मशीनों को किया आग के हवाले

बीजापुर (आरएनएस)। जिले के नैमड थाना क्षेत्र के एनएच पर स्थित मिंगाचल बस्ती में माओवादियों ने बीती रात 9 बजे के आसपास बड़ी घटना को अंजाम देते हुए 6 टिप्पर और दो जेसीबी मशीनों को आग के हवाले कर दिया है। वाहनों में आगजनी की खबर के बाद पहली बार जिला मुख्यालय से फायर ब्रिगेड की दो गाड़ी घटना स्थल पहुंच कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया किंतु आग इतनी ज्यादा लग चुकी थी कि सभी वाहने 80 प्रतिशत जल चुकी है। इस घटना के बाद एक बार फिर एनएच में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है।

बिलासपुर गोली कांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार, एक अब भी फरार

बिलासपुर (आरएनएस)। गुरुवार के बिलासपुर के दीपक ज्वेलर्स लूट के असफल प्रयास मामले में पुलिस ने घटना के बाद फरार को दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है वह शालीमार एक्सप्रेस से भागने की कोशिश कर रहा था। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शनिचरी बाजार के पास गोडपारा इलाके में गुरुवार को कट्टे की नोक पर तीन बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान को लूटने का प्रयास किया था। आरोपियों

ने ज्वेलरी दुकान में घुसकर दुकानदार पर गोली चला दी। इस दौरान दुकानदार दीपक सोनी गंभीर रूप से घायल हो गया। किंतु व्यापारी ने हिम्मत दिखाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया और दो आरोपी मौके से फरार हो गए थे। जिसके बाद पुलिस ने चारों ओर नाकेबंदी फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। सूचना पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शालीमार एक्सप्रेस से दूसरे शहर भागने की कोशिश कर रहा था।

बालको के खिलाफ जारी हड़ताल रोकने श्रम न्यायालय ने दिया स्थगन आदेश

कोरबा। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) के खिलाफ बालको कर्मचारी संघ (भारतीय मजदूर संघ संबद्ध इकाई) द्वारा 13 अप्रैल, 2022 से जारी हड़ताल को माननीय श्रम न्यायालय, कोरबा ने रोकने का आदेश दिया है। माननीय श्रम न्यायालय के समक्ष बालको ने आवेदन प्रस्तुत किया था ताकि बालको संघ के परसाभाठा गेट के समक्ष जारी हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन पर सुनवाई की जा सके। न्यायालय ने मामला क्र. 05/सीजीआईआर/2022 पंजीबद्ध करते हुए सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है कि जारी हड़ताल को आगामी पेशी दिनांक 22 अप्रैल,



2022 से पूर्व रोक दिया जाए। अपने एकपक्षीय स्थगन आदेश में माननीय श्रम न्यायालय ने यह भी कहा है कि चूंकि आवेदक संस्थान में हड़ताल से औद्योगिक, सुरक्षा व शांति एवं व्यवस्था प्रभावित होगी, परिणामस्वरूप हड़ताल से आवेदक संस्थान में एल्यूमिनियम उत्पादन एवं विनिर्माण तथा विद्युत उत्पादन का कार्य भी प्रभावित हो जाएगा। न्यायालय के आदेश की सूचना प्रति बालको कर्मचारी संघ को उपलब्ध करा दी गई है। बालको प्रबंधन ने बालको कर्मचारी संघ से

यह कहा है कि वे अपने संगठन द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। बालको ने यह स्पष्ट किया है कि प्रबंधन ने सदैव ही श्रमिकों के हितों में अपनी नीतियां पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से तैयार करते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। बालको प्रबंधन ने यह अपील की है कि कामगार किसी भी उरुसावे में न आए। अपने कार्यस्थलों पर उपस्थित होकर बालको संघ के सुचारू प्रचालन में अपना योगदान सुनिश्चित करें। एक-जुट होकर औद्योगिक शांति एवं सौहार्द के जरिए बालको परिवार के नागरिक देश की उन्नति प्रगति में अपना योगदान कर सकते हैं।

Social Justice Union advertisement with logo, contact info, and text about legal services.